तटीय क्षेत्रों के अपूर्व विकास से पर्यटन व व्यापार के नए परिवेश का सृजन

सर्व सहकार सर्व साकार

सहकार जागरण

वर्ष : 03 – अंक : 03 – जून 2025

डेयरी क्षेत्र में बनेंगी तीन नई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी

नीली क्रांति से मजबूत हो रहा सहकारी मत्स्य पालन 14

'ऑपरेशन सिंदूर' से आतंक के खिलाफ लड़ाई को लेकर नया संकल्प 16

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ

सर्व सहकार सर्व साकार
सहकार जागरण
जून 2025, अंक 03, वर्ष 03

संपादक मंडल

प्रधान संपादक
डॉ. सुधीर महाजन
संपादक
राजीव शर्मा
समूह संपादक
वेद प्रकाश सेतिया

सहकार जागरण से जुड़ी प्रतिक्रिया, सुझाव या आलेख देना चाहते हैं तो हमें ई-मेल करें:
sahakarjagran@gmail.com
ncui.pub@gmail.com
प्रकाशन का अंतिम निर्णय संपादक मंडल का होगा।
निदेशक (प्रकाशन/जनसंपर्क),
एनसीयूआई
एनसीयूआई कैंपस, 3, अगस्त क्रांति मार्ग, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली: 110016

सहकार जागरण से जुड़ने के अन्य पते:
MINISTRY OF COOPERATION
NCUI हाट
CEAS-LMS

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा 'सहकार जागरण' पत्रिका का सम्पादन एवं प्रकाशन किया जाता है, और इस पत्रिका के प्रकाशन के किसी भी हिस्से की सामग्री की प्रतिलिपि, पुन: उत्पादन या पुनर्वितरण संपादक पैनल और सामग्री के लेखक/लेखकों जैसा भी लागू हो, उनकी लिखित सहमति के बिना कोई भी व्यक्ति, संगठन या पार्टी नहीं कर सकती है। पत्रिका में प्रदर्शित सामग्री तथा आंकड़ें प्राथमिक और अनुषंगी स्रोतों (उद्योग विशेषज्ञ, अनुभवी व्यक्तियों, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार आदि) से लिए गए हैं। पत्रिका में उपलब्ध आंकड़ों और रिपोर्टों के स्रोतों के संबंध में, न तो भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ और न ही इसके कर्मचारी किसी भी त्रुटि के लिए जिम्मेदार हैं और न ही इस संबंध में उनका कोई कानूनी दायित्व है।

05
आवरण कथा
डेयरी क्षेत्र में बनेंगी तीन नई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी
श्वेत क्रांति 2.0 के तहत डेयरी क्षेत्र में सहकारी समितियों की भूमिका बढ़ाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना सरकार का संकल्प है। सहकारिता ग्रामीण विकास का मूल मंत्र है। सहकारी डेयरी क्षेत्र लाखों ग्रामीण परिवारों को आजीविका का महत्वपूर्ण साधन उपलब्ध कराता है।

17
भारत की रणनीति, मारक क्षमता और सटीक जानकारी से पूरी दुनिया आश्चर्यचकित
भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पहलगाम आतंकी हमले का उचित जवाब दिया है। इससे पूरी दुनिया को एक मजबूत संदेश गया है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा विशिष्ट इनपुट के बाद आतंकी कैंपों के खिलाफ चलाया गया यह ऑपरेशन पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की 'जीरो टालरेंस' की नीति का परिचायक है।

आतंक के खिलाफ हमारी जीरो टालरेंस नीति का प्रमाण है ऑपरेशन सिंदूर — 18
जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ चट्टान की तरह खड़ी है मोदी सरकार — 20
विकसित भारत के निर्माण में एकजुट हैं 140 करोड़ भारतीय — 22
फॉरेंसिक ऑडिट से बड़े-बड़े आर्थिक घोटालों का हो रहा खुलासा — 24
आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना — 26
जल आपूर्ति के लिए पाइप लाइनों में लीकेज रोकने के साथ जल वितरण संरचना को और सुदृढ़ बनाने की जरूरत — 27
अन्न भंडारण से जुड़ेंगे ज्यादा से ज्यादा पैक्स — 28

29
त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बोर्ड गठित

सहकारिता की बढ़ रही सामर्थ्य

देश में सहकारिता आंदोलन नई ऊंचाइयों को छूने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नतृत्व में भारत सहकारी क्षेत्र को ग्रामीण भारत की समृद्धि का प्रमुख माध्यम बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इस दिशा में बहुत से अभिनव पहल किए गए हैं, जो सहकारी क्षेत्र को सुदृढ़ और सामर्थ्यवान बनाकर ग्रामीणों की प्रगति का मार्ग आसान बना रहे हैं। देश के पहले सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय देशभर में दो लाख नई सहकारी समितियों के गठन को दिशा दे रहा है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) इस बड़ी पहल का क्रियान्वयन करते हुए 56,500 नई समितियों को डेयरी क्षेत्र में स्थापित कर रहा है। इसके अलावा एनडीडीबी डेयरी क्षेत्र की मौजूदा 46,500 समितियों को भी सुदृढ़ बना रही है। इसी तरह, देश भर में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारी विभाग 25,000 नई प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) का गठन कर रहे हैं। मत्स्य सहकारी समितियों के गठन और विकास की जिम्मेदारी राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) उठा रहा है और इसने 6,000 नई मत्स्य सहकारी समितियां बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। देश में मौजूदा 5,500 मत्स्य सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाकर उनकी उपयोगिता और सामर्थ्य बढ़ाने का काम भी एनएफडीबी कर रहा है। इन प्रयासों से दो लाख पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों के गठन से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सजृन के मार्ग खुलेंगे। इसके साथ ही, प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियों को मजबूत करने और देश के अब तक वंचित रहे क्षेत्रों में सहकारिता के विस्तार के जरिए बदलाव लाने वाले इन पहलों से ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि सुनिश्चित होगी। ये पहल वास्तव में सहकारी आंदोलन की नींव को मजबूत करने के सरकार के दूरदर्शी दृष्टिकोण को दर्शाते हैं।

यह अत्यंत गौरव का विषय है कि देश ही नहीं, वैश्विक स्तर पर भी भारतीय डेयरी सहकारिता एक सफल सहकार के रूप में स्थापित हो चुकी है। लेकिन, इसे प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से देश के अब तक अछूते रहे क्षेत्रों में भी विस्तृत करने की जरूरत है। उसकी भरपाई करने की दिशा में सहकारिता मंत्रालय के साथ ही एनडीडीबी की पहल रंग ला रही है। यहां यह भी जरूरी है कि कमजोर सहकारी समितियों पर भी समान रूप से ध्यान दिया जाए, जहां उन्नति की असीम संभावनाएं हैं। डेयरी के माध्यम से ग्रामीण पशुपालक किसानों और विशेष रूप से महिलाओं के जीवन को उन्नत बनाया जा सकता है। हालिया दिनों में गांवों में विकास और बदलाव की गवाही दे रहीं 1.22 लाख से अधिक लखपति दीदियां सरकार के इन प्रयासों की उपलब्धियों को प्रमाणित कर रही हैं।

दरअसल, सहकारिता मंत्रालय के गठने के साथ ही सहकारी क्षेत्र को व्यापक बनाने और इसमें लोगों की सहभागिता बढ़ाने और इसे रोजगार उन्मुख बनाने की दिशा में व्यापक पहल हुए हैं। इससे सहकारी समितियां 25 से अधिक योजनाओं से जुड़कर कार्य कर रही हैं और रोजगार सजृन की नई संभावनाओं का लाभ उठा रही हैं। पैक्स के मॉडल बायलॉज लागू होने से पैक्स इन व्यवसायिक गतिविधियों संचालित करने में सक्षम हुए हैं और डेयरी, मत्स्य, अन्न भंडारण, गोदाम, बीज, एलपीजी- सीएनजी पंप वितरक, कॉमन सर्विस सेंटर और किसान उत्पादक संगठन आदि के रूप में काम करने में सक्षम हुए हैं। सरकार के इन पहलों से पैक्स को आय सजृन के नए अवसर मिल रहे हैं और उनकी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और सुधार हो रहा है। इससे ग्रामीण भारत में विकास और बदलाव की मुहिम तेज हुई है। इन बदलावों से सहकारी समितियां निश्चित रूप से उन्नत होंगी और समाज के दुर्बल वर्ग को आगे बढ़ाने और किसानों के लिए वरदान साबित होंगी। जैसा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री शाह ने कहा भी है कि दो लाख नए पैक्स बनने के बाद फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज के माध्यम से किसानों की उपज को वैश्विक बाजार में पहुंचाना बड़ा सरल हो जाएगा।

जय सहकार

पिछले 11 वर्षों में हमारी सरकार ने युवा शक्ति को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। नई शिक्षा नीति के साथ कौशल विकास और स्टार्ट-अप्स पर फोकस से हमारे युवा 'विकसित भारत' के संकल्प के अहम भागीदार बने हैं। ये हमारे लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि आज देश का युवा राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

आपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति, आसूचना एजेंसियों की सटीक सूचना और हमारी तीनों सेनाओं की अचूक मारक क्षमता का अद्वितीय प्रतीक है। देशवासियों को अपनी तीनों सेनाओं, सीमा सुरक्षा बल और सुरक्षा एजेंसियों पर गर्व है।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

रेहड़ी-पटरी वालों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है पीएम स्वनिधि योजना ! योजना के अंतर्गत अब तक बिना किसी गारंटी के 68 लाख से अधिक रेहड़ी-पटरी वालों के लिए 14,246 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि के 98.29 लाख से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं।

श्री कृष्ण पाल गूर्जर
केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा समग्र देश में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सहकारिता क्षेत्र इस दिशा में विशेष प्रयास कर रहा है।

श्री दिलीप संघाणी
अध्यक्ष, एनसीयूआई एवं इफको

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहकारिता को भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास की आधारशिला के रूप में देखते हैं। उनका मार्गदर्शक सिद्धांत 'सहकार से समृद्धि' इस दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। सहकारी संस्थाएं भारत की सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा हैं और किसानों, महिलाओं एवं ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने का एक सशक्त माध्यम भी हैं।

सहकारिता मंत्रालय
भारत सरकार

डेयरी क्षेत्र में बनेंगी तीन नई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी

सहकार जागरण टीम

- सहकारी डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी विषय पर आयोजित बैठक में हुआ फैसला
- श्वेत क्रांति 2.0 के तहत सहकारी डेयरी क्षेत्र में सतत विकास और सर्कुलर अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर
- दुग्ध संघों एवं सहकारी समितियों को सशक्त बनाने और डेयरी प्रसंस्करण बढ़ाने पर होगा जोर

श्वेत क्रांति 2.0 के तहत डेयरी क्षेत्र में सहकारी समितियों की भूमिका बढ़ाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना सरकार का संकल्प है। सहकारिता ग्रामीण विकास का मूल मंत्र है। सहकारी डेयरी क्षेत्र लाखों ग्रामीण परिवारों को आजीविका का महत्वपूर्ण साधन उपलब्ध कराता है। इसे और आगे बढ़ाने और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना को साकार करने के लिए सहकारी डेयरी क्षेत्र के लिए तीन नई बहुराज्यीय सहकारी समितियां बनाने का निर्णय लिया गया है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में 'सहकारी डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी' विषय

पर हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में यह फैसला किया गया। पहली समिति पशु आहार निर्माण, रोग नियंत्रण और कृत्रिम गभार्धान पर काम करेगी। दूसरी, गोबर प्रबंधन के मॉडल विकसित करेगी और तीसरी सहकारी समिति मृत मवेशियों के अवशेषों के सर्कुलर उपयोग को बढ़ावा देगी।

श्री शाह ने बैठक में कहा, 'जब हम श्वेत क्रांति 2.0 की ओर अग्रसर हैं, तो हमारा लक्ष्य केवल डेयरी सहकारिता का विस्तार करना और उन्हें कुशल एवं प्रभावी बनाना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि डेयरी के एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना चाहिए जो टिकाऊ हो और सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता हो। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए एकीकृत सहकारिता नेटवर्क का सृजन करना होगा ताकि अधिकांश कार्य पारस्परिक सहयोग और सहकारिताओं के बीच में ही हो।'

दुग्ध सहकारी समितियों को सशक्त बनाने पर जोर

बैठक में श्री शाह ने इस बात पर विशेष बल दिया कि दुग्ध संघों एवं सहकारी समितियों को सशक्त बनाने तथा डेयरी संयंत्रों में खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। साथ ही, वैज्ञानिक मॉडल के माध्यम से कार्बन क्रेडिट का प्रत्यक्ष लाभ किसानों तक पहुंचाया जाए। ये सभी प्रयास न केवल किसानों की आय में वृद्धि करेंगे, बल्कि डेयरी क्षेत्र को अधिक सतत एवं पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे। सहकारी डेयरी समितियां दुग्ध क्षेत्र में दूध उत्पादन और विपणन के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ये समितियां छोटे किसानों को स्थिर बाजार, ऋण सुविधा, पशु चिकित्सा और प्रजनन जैसी सेवाएं प्रदान कर न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर रही हैं, बल्कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर उन्हें सशक्त भी बना रही हैं।

श्री शाह ने कहा कि हमें मिलकर 'सस्टेनेबिलिटी से सर्कुलरिटी' तक का सफर

नई समितियों के लाभ

- पहली समिति पशु आहार निर्माण, रोग नियंत्रण और कृत्रिम गभार्धान को देगी बढ़ावा
- दूसरी समिति गोबर प्रबंधन मॉडल को करेगी विकसित
- तीसरी समिति मृत मवेशियों के अवशेषों के सर्कुलर उपयोग को बढ़ाएगी

देश में प्रमुख डेयरी सहकारिताएं

- आंध्र प्रदेश डेरी विकास सहकारी संघ लिमिटेड (एपीडीडीसीएफ)
- बिहार स्टेट कोआपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड (सीओएमएफइडी)
- गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (जीसीएमएमएफ)
- हरियाणा डेरी विकास सहकारी संघ (एचडीडीसीएफ)
- हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड (एचपीएससीएमपीएफ)
- कर्नाटक कोआपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड (केएमएफ)
- केरल राज्य सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड (केसीएमएमएफ)
- मध्य प्रदेश राज्य सहकारी डेरी फेडरेशन लिमिटेड (एमपीसीडीएफ)
- महाराष्ट्र राज्य सहकारी मर्यादित दुग्ध महासंघ (महासंघ)
- उड़ीसा राज्य सहकारी मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड (ओएमएफइडी)
- प्रादेशिक सहकारी डेरी फेडरेशन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश) (पीसीडीएफ)
- पंजाब स्टेट कोआपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड (मिल्कफेड)
- राजस्थान सहकारी डेरी फेडरेशन लिमिटेड (आरसीडीएफ)
- तमिलनाडु कोआपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड (टीसीएमपीएफ)
- पश्चिम बंगाल सहकारी मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन (डब्ल्युबीसीएमपीएफ)
- छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन

तय करना है जो बहुआयामी होगा। डेयरी क्षेत्र में निजी क्षेत्र जिस तेजी के साथ विकास कर रहा है उसे किसानों और पशु पालकों के सहयोग से सहकारी संस्थाएं करेंगी। इसमें तकनीकी सेवाएं, पशु आहार, कृत्रिम गभार्धान, पशु रोग नियंत्रण, गोबर प्रबंधन तथा डेयरी और कृषि से संबद्ध क्षेत्रों में संकलन से लेकर प्रोसेसिंग तक की गतिविधियां शामिल हैं। डेयरी क्षेत्र में अमूल जैसे सफल सहकारी मॉडल का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों और हितधारकों के साथ मिलकर न केवल डेयरी क्षेत्र में इस सफलता को आगे बढ़ा रहा है, बल्कि ग्राम स्तरीय सहकारी समितियों को अन्य गतिविधियों से भी जोड़कर उन्हें विस्तारित और मजबूत कर रहा है। ये सभी प्रयास प्रधानमंत्री के विकसित भारत के लक्ष्य को समेकित रूप से हासिल करने में सहायक सिद्ध होंगे।

श्वेत क्रांति 2.0 को सफल बनाने के लिए सहकारिता और मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय सभी हितधारकों को एक साथ लाया है। इससे अब नीति निर्माण, वित्त पोषण से लेकर ग्राम स्तरीय सहकारिता के गठन और उन्हें बहुउद्देशीय बनाने का कार्य तीव्र गति से हो रहा है। राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (एनडीडीबी) ने सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। एनडीडीबी द्वारा विकसित बायोगैस और गोबर प्रबंधन कार्यक्रम का पूरे देश में विस्तार किया जा रहा है। श्वेत क्रांति के माध्यम से दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ-साथ बायोगैस और जैविक खाद का उत्पादन बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। देश के कुल दूध उत्पादन में सहकारी क्षेत्र की हिस्सेदारी इस समय करीब 14 प्रतिशत है जिसे बढ़ाकर अगले पांच वर्ष में 22-23 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के साथ सहकारी क्षेत्र में दुग्ध प्रोसेसिंग को प्रोत्साहित किया जाएगा।

सहकारिता मंत्रालय की इस समीक्षा बैठक में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल सिंह गुर्जर और श्री मुरलीधर मोहोल सहित सहकारिता सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी, डेयरी और पशुपालन सचिव श्रीमती अलका उपाध्याय, एनडीडीबी अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह और नाबार्ड के अध्यक्ष श्री शाजी केवी ने भी अपने विचार रखे। श्री शाह ने सहकारिता क्षेत्र के उन्नयन के लिए कार्य कर रही राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), एनडीडीबी और नाबार्ड की सराहना करते हुए कहा कि इनके परस्परिक सहयोग से निश्चित रूप से सहकारिता को बल मिलेगा और किसान केंद्रित योजनाओं को पूरे भारत में लागू किया जा सकेगा। सहकारिता क्षेत्र की शीर्ष संस्थाओं की मदद से निचले स्तर पर डेयरी क्षेत्र में तेजी से विकास की संभावना बढ़ी है। ■

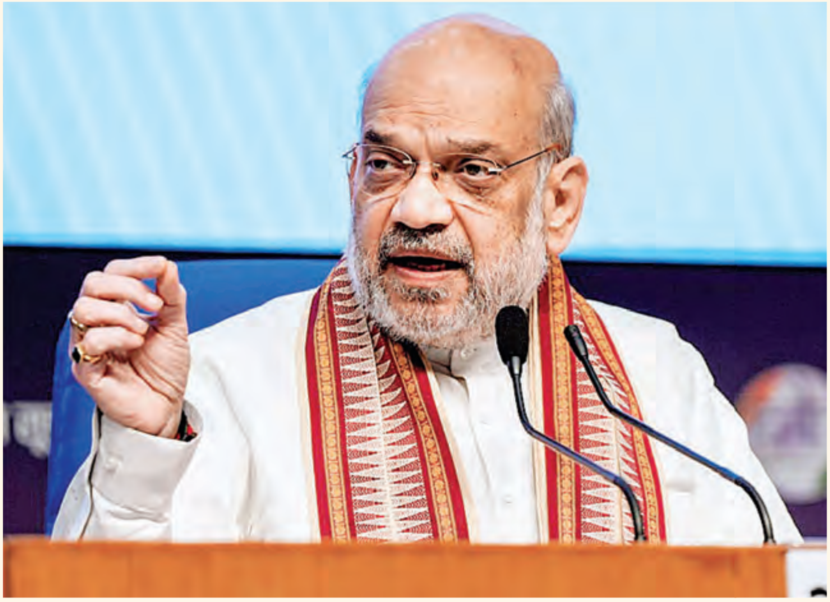

भारत का सहकारी डेयरी उद्योग विश्व में अद्वितीय है। देश में प्रति किसान केवल दो-तीन गायों के छोटे स्तर के डेयरी प्रणाली और मुख्य रूप से फसल अवशेष आधारित पशु आहार के बावजूद भारत वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश बन गया है। भारत में व्यापक स्तर पर संचालित रिकॉर्डिंग कार्यक्रम और अनुसंधान परियोजनाएं, गाय, भैंस और अन्य पशुधन प्रजातियों की अब तक कम पहचानी गई नस्लों पर बहुमूल्य डेटा प्रदान कर रही हैं, जिससे वैश्विक शोधकर्ताओं का ध्यान आकृष्ट हो रहा है।

डेयरी सहकारिता से हो रहा ग्रामीण विकास समृद्ध हो रहीं महिलाएं

- **‘सहकार से समृद्धि’ को साकार करते हुए 1.22 लाख से अधिक महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बनकर हुईं आत्मनिर्भर**
- **सहकारी क्षेत्र के विकास और विस्तार से किसानों के जीवन में आ रही खुशहाली, उभर रही ग्रामीण भारत की नई तस्वीर**
- **सहकारी डेयरी उद्योग से हो रहा महिला सशक्तिकरण**

सहकार जागरण टीम

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने और सहकारिता की शक्ति से ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए जिस सहकारिता मंत्रालय को स्थापित किया, वह केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में ग्रामीण भारत में विकास और बदलाव की एक मुहिम के रूप में स्थापित हो रहा है। मंत्रालय की अनेक बहुआयामी पहलों के माध्यम से किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के जीवन में समृद्धि के नए द्वार खुल रहे हैं। डेयरी सहकारिता भी इस दिशा में अहम भूमिका निभा रही है। श्री शाह के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) देश में सहकारी विकास एवं सहकारिता शासन से संबंधित कार्यक्रमों को विस्तार दे रही है, जिससे आत्मनिर्भर, संयुक्त स्वामित्व वाली, लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित एवं प्रोफेशनल ढंग से प्रबंधित सहकारी संस्थाओं का निर्माण हो रहा है।

एनडीडीबी अपने सदस्यों की सामाजिक-आर्थिक उन्नति एवं विकास और सांस्कृतिक आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में अहम भूमिका निभाते हुए देशभर की सहकारिताओं को तकनीकी एवं परामर्श सहयोग के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में योगदान कर रही है। यह संगठन उत्पादक स्वामित्व वाली संस्थाओं को तकनीकी एवं परामर्श सहयोग, संस्थागत निर्माण, दुग्ध संकलन के बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण, सहकारिता में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि के उपाय, तकनीकी एवं नीतिगत परामर्श के लिए संपर्क और डेयरी उत्पादों के मार्केटिंग में सहयोग एवं नवाचार व परियोजना प्रबंधन के जरिए महत्वपूर्ण दूध संघों की प्रबंधन

गतिविधियों को सहायता जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं देकर सहकारिता को नया विस्तार दे रहा है। इस तरह, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड डेयरी क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देकर सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती प्रदान कर रहा है और ग्रामीण भारत के विकास और देश की सामाजिक-आर्थिक प्रगति में निर्णायक भूमिका निभा रहा है।

डेयरी क्रांति से गांवों में तेज हुई महिला सशक्तिकरण की मुहिम

सहकारिता के विकास से महिलाओं ने ऐतिहासिक रूप से डेयरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे दूध उत्पादक संगठनों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और गांवों में सशक्तिकरण की एक मिसाल पेश करते हुए देश में डेयरी कोऑपरेटिव के जरिए 1.22 लाख 'लखपति दीदियां' बनीं हैं। डेयरी में मवेशियों के प्रबंधन, दूध निकालने और दूध की गुणवत्ता चेक करने जैसे कार्यों में महिलाओं की सहभागिता बढ़ी है और महिलाओं को वाणिज्यिक डेयरी उद्यमों के शीर्ष पर रखने, उन्हें निर्णय लेने वालों और व्यावसायिक नेताओं में बदलने में एनडीडीबी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और डेयरी क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया है। देश में संचालित शीर्ष 22 सहकारी दूध उत्पादक संगठनों (एमपीओ) में से 17 विशेष रूप से महिलाओं के स्वामित्व में हैं और महिलाओं के नेतृत्व वाले बोर्ड ही उनकी रणनीतिक दिशा तय करते हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इन दुग्ध संगठनों में से 18 की अध्यक्षता महिलाएं ही कर रही हैं।

1.22 लाख 'लखपति दीदियां' बनीं आत्मनिर्भर

श्री शाह के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय की पहल का ही असर है कि सहकारिता के विस्तार से महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यम डेयरी क्षेत्र में सफलता को फिर से परिभाषित कर रहे हैं। इस तरह से महिला डेयरी किसानों की परिवर्तनकारी भूमिका जमीनी स्तर पर आर्थिक विकास को उजागर कर रही है। इनमें से कई महिला नेताओं ने वैश्विक मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें यूएसए और फ्रांस में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन भी शामिल हैं। इसका व्यापक और गहरा प्रभाव यह है कि अब महिलाएं डेयरी क्षेत्र के दिन-प्रतिदिन के कामकाज की जिम्मेदारी भी संभालने में निर्णायक भूमिका अदा कर रही हैं। इस क्षेत्र में एक अहम उपलब्धि के रूप में श्रीमती रचना देवधर गोयल ने राजस्थान के अलवर की सखी महिला दुग्ध उत्पादक संस्थाओं (एमपीओ) की मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में दायित्व निभा रही हैं।

> 'श्वेत क्रांति 2.0' की ओर बढ़ते हुए हमारा लक्ष्य केवल सहकारी डेयरी संस्थाओं का विस्तार करना नहीं है, बल्कि ऐसा टिकाऊ और सर्कुलर डेयरी इकोसिस्टम बनाना है जिससे किसानों की आमदनी भी बढ़े और पर्यावरण की भी रक्षा हो।
>
> **श्री अमित शाह**
> **केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री**

सहकारी डेयरी एक व्यवहार्य व लाभदायक आर्थिक गतिविधि

एनडीडीबी के प्रयासों से लाखों दूध उत्पादकों के लिए सहकारी डेयरी को एक व्यवहार्य और लाभदायक आर्थिक गतिविधि बन गया है और भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव ला रहा है। इसके साथ ही इसने भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर और अग्रणी बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। एनडीडीबी दुग्ध उत्पादन से अतिरिक्त आय पैदा करने वाली नवीन गतिविधियों को लागू करके और उन्हें स्थायी आजीविका प्रदान करके डेयरी किसानों को समृद्ध किया है। एनडीडीबी की पहल ने दूध उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाते हुए डेयरी उद्योग को लाखों दूध उत्पादों के लिए एक स्थायी एवं लाभप्रद आर्थिक गतिविधि बनाकर भारत की ग्रामीण व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। नवीन गतिविधियों को क्रियान्वित करते हुए एनडीडीबी डेयरी किसानों तक अपनी पहुंच को बढ़ा रही है तथा उन्हें स्थायी आजीविका प्रदान कर रही है। इन प्रयासों ने दूध उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाते हुए डेयरी उद्योग को लाखों दूध उत्पादों के लिए स्थायी और लाभकारी आर्थिक गतिविधि बना दिया है, जिससे भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ठोस बदलाव हुआ है। ■

देश के सभी गांवों तक होगा सहकारी डेयरी का विस्तार

सहकार जागरण टीम

- कोऑपरेटिव डेयरी की हिस्सेदारी 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 22 प्रतिशत करने का लक्ष्य
- सहकारी क्षेत्र के विस्तार से खुल रहे विकास के स्वर्णिम अवसर

सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से श्वेत क्रांति-2.0 को सफल बनाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। पशुपालकों, दूध उत्पादकों, छोटे व भूमिहीन किसानों की वित्तीय हालत में सुधार के साथ रोजगार के अवसर सृजित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। दुग्ध उत्पादन, संकलन और प्रसंस्करण के क्षेत्र में सहकारिता क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि से इस लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प किया गया है। दूसरी श्वेत क्रांति को सफल बनाने के लिए इससे जुड़े विभिन्न मंत्रालयों का सहयोग भी लिया जा रहा है। इसके लिए देश में एक लाख से अधिक डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटियों के गठन का फैसला किया गया है, ताकि हर गांव तक डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी की पहुंच हो जाए।

ग्राम स्तर पर दुग्ध संकलन केंद्रों की स्थापित करने की योजना को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। साथ ही, मिल्क प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाने के लिए नए हाइटेक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इससे दुग्ध संकलन

परियोजना के लाभ

दूध संकलन, परीक्षण, चिलिंग, लॉजिस्टिक और प्रसंस्करण का ढांचा होगा मजबूत

इन कदमों से डेयरी मूल्य श्रृंखला को मिलेगी मजबूती

छोटे डेयरी किसानों को बाजार पहुंच प्राप्त होगी, उचित एवं लाभकारी मूल्य मिलना सुनिश्चित होगा

प्राथमिक डेयरी सोसाइटियों के नेटवर्क को आगे बढ़ाने में मिलेगी मदद

डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी

और दुग्ध विक्रय में वृद्धि हो सकेगी। दूध की घरेलू मांग के साथ वैश्विक बाजार में दुग्ध उत्पादों की पैठ को मजबूत बनाने की रणनीति तैयार की गई है। मल्टी डेयरी पैक्स (एमपैक्स) को वित्तीय मदद के लिए नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनसीडीसी) ने हाथ बढ़ाए हैं। देश की तकरीबन 10,000 एमपैक्स को वित्तीय मदद उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक सोसाइटी को न्यूनतम 40 हजार रुपए की मदद दी जाएगी।

श्वेत क्रांति 2.0 से दूध संकलन, परीक्षण, चिलिंग, लॉजिस्टिक और प्रसंस्करण का ढांचा मजबूत किया जाएगा जिससे डेयरी मूल्य श्रृंखला सशक्त होगी। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के लिए इसे बूस्टर डोज माना जा रहा है। सहकारिता मंत्रालय की पहल से पशुपालकों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। सहकारिता मंत्रालय ने केंद्रीय पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी मंत्रालय के माध्यम से देश के कुल दुग्ध उत्पादन में डेयरी कोऑपरेटिव की हिस्सेदारी को आगामी पांच वर्षों में अभूतपूर्व वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया है।

दुग्ध क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया है। भारत का वार्षिक दुग्ध उत्पादन 23.9 करोड़ टन से अधिक हो गया है। 2023 तक इसे बढ़ाकर 30 करोड़ टन करने का लक्ष्य तय किया गया है। दुग्ध के वैश्विक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 24.64 प्रतिशत हो गई है। लेकिन इसमें सहकारिता क्षेत्र की हिस्सेदारी सिर्फ 14 प्रतिशत ही है। इसे बढ़ाकर अगले पांच वर्षों में 22 प्रतिशत करना है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) इस लक्ष्य को प्राप्त करने में नोडल भूमिका निभाएगा। योजना के तहत दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के साथ अधिक से अधिक पशुपालकों को डेयरी कोऑपरेटिव से जोड़ा जाएगा। ■

"श्वेत क्रांति 2.0 महिला स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण का काम करेगा। दूध के उत्पादन और खास कर सहकारी डेयरियों के साथ माताएं-बहनें जुड़ी हुई हैं, जिन्हें आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने का काम डेयरी क्षेत्र जितना कोई और नहीं कर सकता। कई राज्यों में ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। गुजरात में 36 लाख बहनें डेयरी क्षेत्र से जुड़कर 60,000 करोड़ रुपए का व्यापार करती हैं। अमूल पूरे विश्व में खाद्य क्षेत्र में सबसे विश्वसनीय ब्रांड बन गया है।"

- श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

श्वेत क्रांति 2.0 आजीविका से जुड़ी

2030 तक कुल दूध उत्पादन 23 करोड़ टन से बढ़ाकर 30 करोड़ टन करने का लक्ष्य

- श्वेत क्रांति 2.0 से डेयरी क्षेत्र में दूध का संकलन बढ़कर हो जाएगा डेढ़ गुना
- देश के डेयरी से जुड़े सभी परिवारों को सहकारिता से जोड़ना प्रमुख उद्देश्य
- श्वेत क्रांति 2.0 के दौरान लगभग 2.7 लाख ग्राम पंचायतें पैक्स से जुड़ेंगी
- एक लाख डेयरी सहकारी सोसाइटियों की स्थापना की योजना

गुजरात के भुज में विकास परियोजनाओं का शुभारंभ कर बोले प्रधानमंत्री श्री मोदी

तटीय क्षेत्रों के अपूर्व विकास से पर्यटन व व्यापार के नए परिवेश का सृजन

सहकार जागरण टीम

भारत की सौर क्रांति में कच्छ की केंद्रीय भूमिका है। यह दुनिया में हरित ऊर्जा के सबसे बड़े केंद्र के रूप में उभर रहा है। कार, बस और स्ट्रीट लाइट जल्द ही हरित हाइड्रोजन से संचालित होंगी, जिससे भारत के ऊर्जा परिदृश्य में क्रांति आएगी। इन तथ्यों को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के भुज में 53,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित करने के दौरान व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हरित हाइड्रोजन में परिवर्तनकारी क्षमता है और यह भविष्य का ईंधन है। कच्छ के तेज विकास के लिए बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास के लिए जिन परियोजनाओं को शुरू किया जा रहा है, वे भारत के एक प्रमुख नीली अर्थव्यवस्था और हरित ऊर्जा के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। इस क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं में से एक विकसित की जा रही है। श्री मोदी ने कहा कि खावड़ा परिसर की स्थापना के साथ कच्छ वैश्विक ऊर्जा मानचित्र पर मजबूती से स्थापित हो गया है। यहां कांडला देश के तीन हरित हाइड्रोजन केंद्रों में से एक है। उन्होंने कच्छ में एक नए हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखने की घोषणा की और कहा कि इस संयंत्र में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक पूरी तरह से 'मेड इन इंडिया' है।

नागरिकों के लिए बिजली की लागत कम करते हुए पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते

- **प्रधानमंत्री ने 53,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन**
- **व्यापार और पर्यटन के महत्वपूर्ण केंद्र कच्छ की आने वाले समय में होगी और बड़ी भूमिका**
- **हरित हाइड्रोजन में परिवर्तनकारी क्षमता है और यह भविष्य का ईंधन है**

हुए श्री मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के शुभारंभ का जिक्र किया, जिससे गुजरात में लाखों परिवार पहले ही लाभान्वित हो चुके हैं। उन्होंने तटीय क्षेत्रों के आर्थिक महत्व पर जोर देते हुए कहा कि समुद्री समृद्धि कई देशों के विकास में एक महत्वपूर्ण कारक रही है। भारत की समृद्ध विरासत और ऐतिहासिक व्यापार

एवं विकास में प्राचीन बंदरगाह शहरों ढोला वीरा और लोथल की भूमिका का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ''इस विरासत से प्रेरित होकर, सरकार बंदरगाहों के आसपास शहरों का विस्तार करके बंदरगाह-आधारित विकास पर आधारित अपने दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रही है।'' उन्होंने कहा कि भारत समुद्री भोजन, पर्यटन और व्यापार को शामिल करते हुए एक नए तटीय इकोसिस्टम को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए महत्वपूर्ण निवेश किए जा रहे हैं, जिसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। पहली बार प्रमुख बंदरगाहों ने सामूहिक रूप से एक साल में रिकॉर्ड 15 करोड़ टन कार्गो संभाला है, जिसमें कांडला पोर्ट की अहम भूमिका रही है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के समुद्री व्यापार के लगभग एक तिहाई हिस्से का प्रबंधन कच्छ के बंदरगाहों द्वारा किया जाता है। उन्होंने कहा कि कांडला और मुंद्रा बंदरगाहों पर क्षमता और कनेक्टिविटी को लगातार बढ़ाया जा रहा है। समुद्री क्षेत्र पर सरकार के विशेष फोकस का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत न केवल घरेलू जरूरतों के लिए, बल्कि वैश्विक मांग के लिए भी बड़े जहाजों का निर्माण करेगा। इन पहलों से समुद्री क्षेत्र में देश के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

विकास की एक प्रेरक शक्ति बनी कच्छ की विरासत

कच्छ की विरासत पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने इसे अब क्षेत्र के विकास के पीछे एक प्रेरक शक्ति बताया। उन्होंने भुज में कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, चीनी मिट्टी की चीजें और नमक उत्पादन सहित विभिन्न उद्योगों में हुई उल्लेखनीय वृद्धि का जिक्र किया। कच्छ कढ़ाई, ब्लॉक प्रिंटिंग, बांधनी कपड़े और चमड़े के काम जैसे पारंपरिक शिल्प की व्यापक मान्यता पर जोर देते हुए उन्होंने हथकरघा कला के एक जीवंत संग्रहालय के रूप में भुजोडी गांव की तारीफ की। श्री मोदी ने कच्छ की अजरख

छपाई की अनूठी परंपरा का जिक्र किया, जिसे अब भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग भी मिल गया है। आदिवासी परिवारों और कारीगरों के लिए इस विशेष पहचान से उनकी सांस्कृतिक पहचान और शिल्प कौशल को मजबूती मिलती है।

महान स्वतंत्रता सेनानी श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा सहित क्रांतिकारियों और शहीदों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नर्मदा नदी का पानी कच्छ क्षेत्र में पहुंचते हुए देखना उनके लिए खुशकिस्मती की बात है। उन्होंने कच्छ के किसानों के अटूट दृढ़ संकल्प और जज्बे को याद किया और कहा कि उनके अथक परिश्रम से कच्छ व्यापार, वाणिज्य और पर्यटन के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में खड़ा है। आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र की भूमिका और भी बड़ी होगी। किसानों के परिश्रम और गुजरात में भूजल स्तर को बेहतर बनाने में नर्मदा जल और सरकार के समर्पित प्रयासों से हुए बदलावों का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कच्छ के भाग्य को नया आकार देने में केवड़िया से मोदकुबा तक फैली नहर की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब कच्छ से आम, खजूर, अनार, जीरा और ड्रैगन फ्रूट जैसी कृषि उपज वैश्विक बाजारों तक पहुंच रही है। जहां अतीत के दिनों में यहां सीमित अवसरों के कारण मजबूरन पलायन होता था, वहीं उल्लेखनीय प्रगति के फलस्वरूप स्थानीय युवाओं को अब कच्छ में ही रोजगार मिल रहा है, जिससे क्षेत्रीय समृद्धि बढ़ रही है। ■

पर्यटन क्षेत्र युवाओं के रोजगार का बड़ा माध्यम बनेगा

श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना उनकी सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जो बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि कच्छ अपने समृद्ध इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता के साथ इस क्षेत्र में विस्तार के लिए अच्छी स्थिति में है। कच्छ का रण उत्सव लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है और इससे आने वाले वर्षों में कच्छ के पर्यटन उद्योग में और वृद्धि होगी। यहां धोरडो गांव ने वैश्विक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में अंतरराष्ट्रीय पहचान हासिल की है और मांडवी का समुद्री तट पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण के रूप में उभर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद और भुज के बीच नमो भारत रैपिड रेल क्षेत्र में पर्यटन को और बढ़ावा देगी।

नीली क्रांति से मजबूत हो रहा सहकारी मत्स्य पालन

सहकार जागरण टीम

सहकारिता के माध्यम से मत्स्य पालन क्षेत्र की तस्वीर बदलने की केंद्र सरकार की पहल का असर दिखने लगा है। इससे न केवल उत्पादन में वृद्धि हो रही है, बल्कि मछुआरों का जीवन स्तर भी सुधर रहा है। देश की अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह राष्ट्रीय आय, निर्यात, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा के साथ-साथ रोजगार सृजन में भी योगदान देता है। मत्स्य पालन क्षेत्र को 'सूर्योदय क्षेत्र' के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह देश के लगभग 3 करोड़ लोगों की आजीविका का साधान है, खासकर वंचित और कमजोर समुदायों के लोगों की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए पिछले 10 वर्षों में सरकार द्वारा उठाए गए कदम और उनके असर की समीक्षा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की जिसमें उन्होंने इस क्षेत्र को और आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री ने मछली संसाधनों के बेहतर उपयोग और मछुआरों को सुरक्षा निर्देश देने के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग पर जोर दिया। साथ ही, स्मार्ट बंदरगाहों और बाजारों के माध्यम से इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण, पकड़ी गई मछलियों के परिवहन और उसकी मार्केटिंग में ड्रोन के उपयोग का सुझाव दिया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में एग्रो टेक की तरह ही मत्स्य पालन क्षेत्र में भी मछली प्रौद्योगिकी को अपनाया जाना चाहिए ताकि उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन की कार्य प्रणालियों में सुधार हो सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत सरोवरों में मत्स्य उत्पादन से न केवल इन जल निकायों की जीविका में सुधार होगा, बल्कि मछुआरों की आजीविका में भी सुधार होगा। आय सृजन के एक अवसर के रूप में सजावटी मछली पालन को भी बढ़ावा देने पर भी उन्होंने जोर दिया।

- **मत्स्य पालन क्षेत्र में पैक्स और एफएफपीओ के गठन को केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय दे रहा बढ़ावा**
- **दो लाख नए पैक्स बनाने के तहत 11 हजार से ज्यादा मत्स्य सहकारी समितियां बनाने का है लक्ष्य**
- **1500 से ज्यादा मत्स्य सहकारी समितियों का हो चुका है गठन जिससे बदल रही मछुआरों की जिंदगी**
- **मोदी सरकार के पहलों से पिछले 10 वर्षों में मछली उत्पादन और निर्यात में दोगुने से ज्यादा की वृद्धि**

मत्स्य उत्पादन बढ़ाने पर जोर

पिछले 10 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार ने मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं। इनमें नीली क्रांति योजना, मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई), प्रधानमंत्री मत्स्य समृद्धि योजना (पीएम-एमकेएसएसवाई) और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की योजनाएं शामिल हैं। इसके परिणामस्वरूप 2024-25 में 9 प्रतिशत से अधिक की क्षेत्रीय वृद्धि दर के साथ कुल (अंतर्देशीय और समुद्री) वार्षिक मछली उत्पादन 195 लाख टन पर पहुंच गया है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 184.02 लाख टन था। वित्त वर्ष 2013-14 के 95.79 लाख टन की तुलना में पिछले 10 वर्ष में उत्पादन में दोगुने से भी ज्यादा की

प्रधानमंत्री ने मत्स्य पालन क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की

टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने का निर्देश

मत्स्य पालन क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाने का निर्देश दिया है। साथ ही, मछली पालकों की आमदनी बढ़ाने के लिए सजावटी मछली पालन को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया है। मत्स्य पालन क्षेत्र को विकसित करने के लिए पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इन कदमों की प्रगति की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक की जिसमें प्रधानमंत्री ने मछली संसाधनों के बेहतर उपयोग और मछुआरों को सुरक्षा निर्देश देने के लिए सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के व्यापक उपयोग पर जोर दिया। स्मार्ट बंदरगाहों और बाजारों के माध्यम से इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण, पकड़ी गई मछलियों के परिवहन और उसके विपणन में ड्रोन के उपयोग पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि आपूर्ति श्रृंखला में मूल्यवर्द्धन के लिए कामकाज की एक स्वस्थ प्रणाली की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने नागरिक उड्डयन के परामर्श से उत्पादन केंद्रों से शहरों एवं कस्बों के बड़े नजदीकी बाजारों तक ताजी मछली ले जाने के लिए तकनीकी प्रोटोकॉल के अनुसार ड्रोन के उपयोग की खोज करने का सुझाव दिया। उन्होंने प्रसंस्करण और पैकेजिंग में सुधार की आवश्यकता सहित निजी क्षेत्र के निवेश को सुविधाजनक बनाने पर भी चर्चा की।

श्री मोदी ने कहा कि कृषि क्षेत्र में एग्रो टेक की तरह ही मत्स्य पालन क्षेत्र में भी मछली प्रौद्योगिकी को अपनाया जाना चाहिए ताकि उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन की कार्य प्रणालियों में सुधार हो सके। अमृत सरोवरों में मत्स्य उत्पादन से न केवल इन जल निकायों की जीविका में सुधार होगा, बल्कि मछुआरों की आजीविका में भी सुधार होगा। उन्होंने कहा कि आय सृजन के एक अवसर के रूप में सजावटी मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। भूमि से घिरे क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक रणनीति तैयार की जानी चाहिए जहां मछली की मांग अधिक है, लेकिन आपूर्ति पर्याप्त नहीं है।

सरकार ने 2015 से विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे कि नीली क्रांति योजना, मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई), प्रधानमंत्री मत्स्य समृद्धि योजना (पीएम-एमकेएसएसवाई) और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से निवेश को बढ़ाकर 38,572 करोड़ रुपए कर दिया है। इससे उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली है। 2024-25 में मछली उत्पादन बढ़कर 195 लाख टन हो गया है।

वृद्धि हुई है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत ने 60,523.89 करोड़ रुपये मूल्य के 17,81,602 टन समुद्री खाद्य पदार्थ का निर्यात किया, जो वित्त वर्ष 2013-14 के 30,213 करोड़ रुपये की तुलना में दोगुने से अधिक की वृद्धि है। केंद्र सरकार ने 2015 से विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों में निवेश को बढ़ाकर 38,572 करोड़ रुपए कर दिया है।

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की पहल से मत्स्य पालन क्षेत्र में प्राथमिक सहकारी समितियों (पैक्स) की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। दो लाख नए पैक्स बनाने के लक्ष्य के तहत वित्त वर्ष 2028-29 तक मत्स्य क्षेत्र में 11 हजार से ज्यादा पैक्स बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में 1,450 मत्स्य सहकारी समितियों (एफसीीएस) का गठन हुआ है, जबकि लक्ष्य 1,051 का था। चालू वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक 74 एफसीीएस का गठन हो चुका है, जबकि लक्ष्य 1,611 एफसीीएस का है। ये समितियां सदस्यों को ऋण सुविधाएं मुहैया कराने के साथ ही समाज के सबसे हाशिए वाले वर्गों की जरूरतों को पूरा करती हैं, उन्हें मार्केटिंग की सुविधाएं प्रदान करती हैं और उन्हें मछली पकड़ने के उपकरण, मछली के बीज एवं चारे की खरीद में भी सहायता करती हैं। इन्हें मत्स्य पालन के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए कौशल उन्नयन पर जोर दिया जा रहा है। मछुआरों के जीवन को समृद्ध बनाने में यह पहल काफी अहम साबित हो रही है। इससे उनकी आमदनी बढ़ाने में मदद मिली है। ■

'ऑपरेशन सिंदूर' से आतंक के खिलाफ लड़ाई को लेकर नया संकल्प

सहकार जागरण टीम

हमारा पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है और आक्रोश से भरा हुआ एवं संकल्पबद्ध है। आज हर भारतीय का यही संकल्प है कि हमें आतंकवाद को खत्म करना ही है। 'ऑपरेशन सिंदूर' सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, बल्कि हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर भी है, जिसने पूरे देश को देश-भक्ति के भावों से भर दिया है। इस दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। इन विचारों को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले दिनों 'मन की बात' कार्यक्रम के दौरान देशवासियों से साझा किया। उन्होंने कहा कि वास्तव में जितने सटीक ढंग से हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वह अद्भुत है। अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि हमारे जवानों ने आतंक के अड्डों को तबाह किया, जो कि उनके अदम्य साहस से ही संभव हुआ। इस आपरेशन में भारत में बने हथियारों, उपकरणों और टेक्नोलॉजी की ताकत भी दिखी, जिसमें 'आत्मनिर्भर भारत' का संकल्प समाहित था। इस अभियान के बाद पूरे देश में 'वोकल फॉर लोकल' को लेकर एक नई ऊर्जा दिख रही है।

इस अभूतपूर्व सैन्य अभियान की सफलता से प्रेरित होकर देश के कई शहरों, गावों और छोटे-छोटे कस्बों में भी तिरंगा यात्राएं निकाली गईं, जिसमें हजारों लोग हाथों में तिरंगा लेकर देश की सेना के प्रति वंदन-अभिनंदन करने निकल पड़े। कितने ही शहरों में 'सिविल डिफेंस वालेंटियर' बनने के लिए बड़ी संख्या में युवक इकठ्ठे हो गए, जिनमें चंडीगढ़ के युवाओं का जोश तो देखने लायक था। प्रधानमंत्री ने कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' ने देश के लोगों को इतना प्रभावित किया है कि कई परिवारों ने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। बिहार के कटिहार, यूपी के कुशीनगर और देश के कई दूसरे शहरों में भी उस दौरान जन्म लेने वाले बच्चों का नाम 'सिंदूर' रखा गया है।

हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है यह सैन्य मिशन 'ऑपरेशन सिंदूर'

जन-मन का जुड़ाव ही भारत की असली ताकत

प्रधानमंत्री ने मन को छू जाने वाली कई बातों का जिक्र करते हुए कहा कि कई बच्चों के माता-पिता ने अपने बच्चों के लिए सिर्फ भारत में बने खिलौने ही लेने का संकल्प किया है और अपने बच्चों में बचपन से ही देश-भक्ति की शुरूआत की ओर कदम बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि कुछ परिवारों ने अपनी अगली छुट्टियां देश के किसी खूबसूरत जगह में ही बिताने का शपथ लिया है। वहीं, कई युवाओं ने संकल्प लिया है कि वे देश में ही शादी करेंगे। बहुत से लोगों ने यह भी संकल्प लिया है कि अब वे लोगों को जो भी गिफ्ट देंगे, वह किसी भारतीय शिल्पकार के हाथों से ही बना होगा। श्री मोदी ने कहा कि सेना के इस ऑपरेशन को लेकर लोग सोशल मीडिया पर कविताएं लिख रहे हैं और संकल्प गीत गा रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चों ने भी पेंटिंग बनाकर अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया, जिनमें बड़े सन्देश छुपे थे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की असली ताकत 'जन-मन का जुड़ाव, जन-भगीदारी' ही है। उन्होंने देशवासियों से यह संकल्प लेने का आह्वान किया कि जीवन में जहां भी संभव हो, देश में बनी चीजों को ही प्राथमिकता दें। यह सिर्फ आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी का भाव है। उन्होंने कहा कि हमारा एक सार्थक कदम भारत की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान बन सकता है। ■

पाकिस्तान और नेपाल के सीमावर्ती राज्यों की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा में बोले श्री अमित शाह

भारत की रणनीति, मारक क्षमता और सटीक जानकारी से पूरी दुनिया आश्चर्यचकित

सहकार जागरण टीम

भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पहलगाम आतंकी हमले का उचित जवाब दिया है। इससे पूरी दुनिया को एक मजबूत संदेश गया है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा विशिष्ट इनपुट के बाद आतंकी कैंपों के खिलाफ चलाया गया यह ऑपरेशन पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की 'जीरो टालरेंस' की नीति का परिचायक है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इन विचारों को नई दिल्ली में पाकिस्तान और नेपाल के सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और विभिन्न सुरक्षा संगठनों के शीर्ष अधिकारियों के साथ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा बैठक के दौरान साझा किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर के पहलगाम में हुए जघन्य आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा था कि देश इस आतंकी हमले के गुनहगारों और आतंकवाद के समर्थकों को कड़ा जवाब देगा। श्री शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, भारत की सीमा, सेना और नागरिकों की ओर आंख उठाने वालों को भारत का मुंहतोड़ जवाब है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने आतंकवादियों से जुड़े नौ ठिकानों पर हमला करके आतंकियों के इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर दिया। भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने इस हमले में लश्कर-ए-तैय्यबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिज्बुल मुजाहिदीन और अन्य आतंकी संगठनों के आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों और हथियार कैंपों व ठिकानों को तहस-नहस कर दिया गया। श्री शाह ने कहा कि इस समय देश ने एकजुटता का जो प्रदर्शन किया है उससे देशवासियों का हौंसला बढ़ा है।

ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का उचित जवाब दिया, जिससे पूरी दुनिया में गया मजबूत संदेश

श्री शाह ने निर्देशित किया कि मॉक ड्रिल के लिए जारी दिशानिर्देशों के तहत सभी राज्य अपनी तैयारियां करें। राज्यों को अति आवश्यक सेवाओं जैसे अस्पताल, अग्निशमन आदि के सुचारु संचालन की व्यवस्था बनाने के लिए प्रेरित करते हुए श्री शाह ने आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित के लिए भी कहा। उन्होंने राज्यों से राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ), सिविल डिफेंस, होमगार्ड्स, एनसीसी आदि को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट रखने को कहा। श्री शाह ने कहा कि नागरिकों और गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से जनभागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश की जाए। सोशल एवं अन्य मीडिया में अवांछनीय तत्वों द्वारा देश विरोधी दुष्प्रचार पर राज्यों को सावधान करते हुए श्री शाह ने कहा कि इन सभी पर कड़ी नजर रखी जाए। उन्होंने ऐसे लोगों पर त्वरित कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों और केंद्रीय एजेंसियों के समन्वय से आगे बढ़ने के निर्देश दिए। श्री

ऑपरेशन सिंदूर

शाह ने संचार व्यवस्था को निर्बाध बनाए रखने के लिए हरसंभव प्रयास के निर्देश दिए। उन्होंने जनता में अकारण भय फैलने से रोकने के लिए राज्यों का आह्वान करते हुए अफवाहों के खिलाफ लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए उचित कदम उठाने के भी निर्देश दिए। श्री शाह ने स्थानीय प्रशासन, सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच समन्वय को और बेहतर करने पर जोर दिया।

इस शीर्षस्तरीय बैठक में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के उपराज्यपाल और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और सिक्किम सरकार के प्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। इसमें केंद्रीय गृह सचिव, निदेशक, आसूचना ब्यूरो, सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के शीर्ष अधिकारियों सहित केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की भी उपस्थिति रही। ■

मुंबई में एक समारोह में बोले केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

आतंक के खिलाफ हमारी जीरो टालरेंस नीति का प्रमाण है ऑपरेशन सिंदूर

सहकार जागरण टीम

- आजादी के बाद राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव में नहीं हो सका था कई समस्याओं का समाधान
- मोदी सरकार ने दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाकर महत्वपूर्ण कामों को पूरा किया
- आतंकियों के घर में घुसकर उनके हेडक्वार्टर को नष्ट किया, मातृशक्ति का मस्तक गौरव के साथ ऊंचा किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने देशवासियों के मन में भारत को 2047 तक पूर्ण विकसित और हर क्षेत्र में सर्वप्रथम बनाने का विश्वास जगाया है। भारत को अब पीछे मुड़कर देखने और रुकने की जरुरत नहीं है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इन तथ्यों को महाराष्ट्र के मुंबई में माधवबाग में स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर की 150वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह के दौरान व्यक्त किया।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में श्री मोदी के 11 साल पूरे हुए हैं और इन वर्षों

> हमारी सैन्य शक्ति ने आतंकियों के घर में घुसकर उनके हेडक्वार्टर को नष्ट कर भारत की मातृशक्ति का मस्तक गौरव के साथ ऊंचा करने का काम किया है।

में उन्होंने देश के विकास की यात्रा को तेज किया है। श्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने ऐसा काम किया है कि भारतीय होने पर देशवासियों को गौरव की अनुभूति हो रही है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद कई दशकों तक देश में राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव में कई समस्याओं का समाधान नहीं हो सका था। इसके एक बड़ा प्रमाण अयोध्या में 550 वर्षों बाद बना भगवान राम का भव्य मंदिर है, जिसे बनाने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि औरंगजेब द्वारा तोड़े गए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाकर काशी विश्वनाथ की महिमा बढ़ाने का कार्य भी उसी दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिणाम है। श्री शाह ने कहा कि दुनियाभर में योग को घर-घर पहुंचाने का काम भी मोदी सरकार ने किया है।

समाज सेवा की प्रखर भावना से हो रहे सामाजिक कार्य

श्री शाह ने कहा कि श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर ट्रस्ट के सभी सदस्य 150 वर्षों से बड़े उद्देश्यों के साथ समाज सेवा की प्रखर भावना को लोगों के बीच पहुंचा रहे हैं। श्री वरजीवनदास और नरोत्तमभाई ने उस जमाने में बहुत बड़ा दिल रखकर समाज के प्रति अपनी उदार भावना का प्रदर्शन करते हुए यह संस्था बनाई थी। श्री शाह ने कहा कि वर्ष 1875 में विदेशी शासन के दौर में एक मंदिर बनाकर उसके माध्यम से सामाजिक चेतना का पुनर्जागरण का कार्य महान लोगों ने पूरा किया। उन्होंने कहा कि इस मंदिर में कई प्रकार की सामाजिक प्रवृत्तियां प्रचलन में हैं और यहां शिक्षा के कार्य के साथ ही गीता का अभ्यास और एक जमाने में संस्कृत विद्यालय भी संचालित होता था। शुचिता, संतुलन और सत्कर्म की त्रिवेणी से माधवबाग ट्रस्ट बना है। यह परंपरा 150 साल से चली आ रही है और हम सबके लिए यह बहुत गौरव की बात है। श्री शाह ने कहा कि हमें यह सोचना होगा कि जब हम 200 साल पूरे होने का उत्सव मनाएं तब इस ट्रस्ट का कैसा स्वरूप होगा। उन्होंने कहा कि क्या हम इस ट्रस्ट को मध्यमवर्गीय समाज की सभी चिंताएं दूर करने वाले एक धार्मिक केंद्र में परिवर्तित कर सकते हैं। श्री शाह ने कहा कि कई प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं देकर मध्यम वर्ग के बीमार नागरिको के लिए एक संजीवनी केंद्र भी यहां बनाया जा सकता है। ■

आतंकी हमले से पीड़ित परिवारों को नौकरी का नियुक्ति पत्र देकर बोले श्री अमित शाह

जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ चट्टान की तरह खड़ी है मोदी सरकार

- **पाकिस्तान द्वारा पुंछ के हमारे रिहायशी इलाकों और निहत्थे नागरिकों पर हमले का भारत ने दिया करारा जवाब, उनके अनेक एयरबेस और निगरानी प्रणाली को किया तबाह**
- **भारत सुरक्षा नीति ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान प्रायोजित आंतकवाद को बहुत स्पष्टता के साथ किया उजागर**

सहकार जागरण टीम

पहलगाम में निर्दोष यात्रियों पर सीमापार से कायराना आतंकी हमला हुआ, जिसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवादी हमले का जवाब तत्परता और कठोरता से दिया। हमारी सेनाओं ने हमारे पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) और पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दिया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इन तथ्यों को जम्मू और कश्मीर के पुंछ में हमले से पीड़ित लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र वितरित करने के दौरान दोहराया। पाकिस्तान द्वारा पुंछ के रिहायशी इलाकों, मंदिरों, गुरुद्वारों और मदरसों पर हुए कायराना हमलों के पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए श्री शाह ने कहा कि इस निंदनीय हमले में हताहत हुए लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने और मुआवजे से जीवन में हुई क्षति की परिपूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन यह जम्मू और कश्मीर सरकार, भारत सरकार और पूरे देश की जनता की भावनाओं का एक प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरा देश इस समय पीड़ित परिवारों के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। जम्मू और कश्मीर के नागरिकों में घाटी से लेकर पुंछ और कठुआ तक देशभक्ति का जो जज्बा उभर कर आया है, उससे पूरे देश की जनता का संबल बढ़ा है। श्री शाह ने जोर देकर कहा कि वर्ष 2014 में जिस गति से जम्मू और कश्मीर में विकास की शुरूआत हुई थी, वह गति आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी।

- **सीमांत क्षेत्रों में मोदी सरकार के बनाए 9,500 से अधिक बंकरों से नागरिकों की जान बचाने में मिली मदद**
- **सरकार के दृढ़ इच्छाशक्ति से लिए निर्णय, एजेंसियों की सटीक सूचना और सेना के अद्भुत साहस व अचूक मारक क्षमता ने सैकड़ों आतंकवादियों का किया सफाया**

श्री शाह ने कहा कि पहली बार भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर स्थित आतंकी संगठनों के

हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया। भारत की जनता की ओर से करारा जवाब के रूप में प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने दृढ़ इच्छाशक्ति से निर्णय लिया और हमारी सुरक्षा एजेंसियों की सटीक सूचना व सेना के अद्भुत साहस एवं अचूक मारक क्षमता ने सैकड़ों की संख्या में आतंकवादियों को ढेर कर दिया। श्री शाह ने जोर देकर कहा कि भारत ने तो आतंकियों पर हमला किया, लेकिन पाकिस्तान ने इसे खुद पर हमला माना और पूरी दुनिया के सामने यह सच उजागर हो गया कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह दे रहा है। श्री शाह ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के एक भी सैन्य या नागरिक संस्थान पर हमला नहीं किया। हमारी सेनाओं ने बेहद सटीक तरीके से संयम बरतते हुए पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी अड्डों को सफलता पूर्वक तहस- नहस कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सेनाएं और सुरक्षाबल हर हमले का जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम हैं।

नागरिकों पर पाकिस्तान के हमले की निंदा कर रही सारी दुनिया

भारत के पाकिस्तान स्थित आतंकी अड्डो पर किए गए हमलों के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने भारत में जम्मू और कश्मीर में रिहायशी इलाकों में गोलीबारी की और जिसका सबसे ज्यादा नुकसान पुंछ में हुआ। पाकिस्तान ने पुंछ के साथ-साथ सभी रिहायशी इलाकों, मंदिरों, गुरुद्वारों और मदरसों पर भी गोलीबारी की। जब पाकिस्तान ने हमारे रिहायशी इलाकों और निहत्थे नागरिकों पर हमला किया, तब भारतीय सेना ने उनके नौ एयरबेस और मारकक्षमता को क्षतिग्रस्त कर एक मजबूत जवाब दिया और इसके कारण उन्हें समझौते के लिए आगे आना पड़ा। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया पाकिस्तान द्वारा नागरिकों पर किए गए हमले की घोर निंदा कर रही है।

श्री शाह ने कहा कि यह पूरा घटनाक्रम मोदी सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को पूरी दुनिया के सामने घटनाओं के आधार पर यह जाहिर करने वाला रहा कि भारत अपनी सेना, नागरिकों और सीमा पर किसी भी प्रकार का आक्रमण सहन नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि पुंछ में कई लोगों के घर और कई व्यापारिक संस्थान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस दौरान पूरा जम्मू कश्मीर प्रशासन हर पल जनता के साथ खड़ा था। प्रशासन ने तत्काल हजारों लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का प्रयास किया और निश्चित रूप से इससे हमारी क्षति बहुत कम हुई। श्री शाह ने कहा कि इस क्षति की प्रतिपूर्ति के लिए भारत सरकार आने वाले कुछ दिनों में इसके लिए एक विशेष पैकेज लाएगी। ■

श्री शाह ने कहा कि श्री मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद बंकर बनाने का निर्णय लिया था और हमारे सीमांत क्षेत्रों में लगभग 9,500 से अधिक बंकर बनाए गए। इससे हमारे नागरिकों की जान बचाने में बहुत मदद मिली। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत सरकार और अधिक बंकर बनाएगी, जिससे आपदा के समय हमारे नागरिकों को बचाया जा सके। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि आतंक और बातचीत, आतंक और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते और न ही खून और पानी एक साथ बह सकते हैं।

गुजरात में विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के दौरान बोले प्रधानमंत्री श्री मोदी

विकसित भारत के निर्माण में एकजुट हैं 140 करोड़ भारतीय

सहकार जागरण टीम

भारत आज निराशा और अंधकार के युग से निकलकर आत्मविश्वास और आशावाद के नए युग में प्रवेश कर चुका है। पिछले कुछ वर्षों में हमने ऐसे अभूतपूर्व और अकल्पनीय निर्णय लिए हैं जो दशकों पुरानी बाधाओं से मुक्त हैं और इससे देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। इन उपलब्धियों को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के दाहोद में 24,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विकास परियोजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन के मौके पर साझा किया। उन्होंने कई अन्य परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करते हुए कहा, '140 करोड़ भारतीय एक विकसित भारत के निर्माण में एकजुट हैं।' श्री मोदी ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और घरेलू उत्पादन और निर्यात दोनों में लगातार वृद्धि हो रही है। भारत अब स्मार्टफोन, ऑटोमोबाइल, खिलौने, रक्षा उपकरण और दवाओं सहित कई तरह के उत्पादों का निर्यात कर रहा है। भारत न केवल रेल और मेट्रो तकनीक का विनिर्माण कर रहा है, बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर निर्यात भी कर रहा है। दाहोद को इस प्रगति का एक प्रमुख उदाहरण बताते हुए उन्होंने कहा कि यहां बनी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री देश की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और यह 9,000 हॉर्स पावर के इंजनों का विनिर्माण करेगी, जिससे भारत की रेलगाड़ियों की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

पिछले 10-11 वर्षों में भारत के रेलवे क्षेत्र के त्वरित विकास का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि मेट्रो सेवाओं के विस्तार और सेमी-हाई-स्पीड ट्रेनों की शुरूआत से पूरे देश में

- **प्रधानमंत्री ने दाहोद में 24,000 करोड़ रुपए से विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास**
- **जनजातीय समाज के विकास के लिए पिछले 11 वर्षों के दौरान किए गए अभूतपूर्व प्रयास**

कनेक्टिविटी में बदलाव हो रहा है। वंदे भारत ट्रेनें भारत के परिवहन नेटवर्क को और सुदृढ़ बनाती हैं, जो कि लगभग 70 रूटों पर चल रही हैं। अहमदाबाद और वेरावल के बीच एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरूआत की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में आधुनिक ट्रेनों का उदय देश की प्रौद्योगिकी में प्रगति की वजह से है। कोच और इंजन अब घरेलू स्तर पर विनिर्मित होते हैं और इससे आयात पर निर्भरता कम होती है। उन्होंने कहा, ''भारत रेलवे उपकरणों के एक प्रमुख निर्यातक के रूप में उभरा है।'' भारत ऑस्ट्रेलिया को मेट्रो कोच और इंग्लैंड, सऊदी अरब और फ्रांस को ट्रेन कोच निर्यात करता है। मैक्सिको, स्पेन, जर्मनी और इटली भी भारत से रेलवे से संबंधित कंपोनेंट आयात करते हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय यात्री कोच मोजाम्बिक और श्रीलंका में उपयोग में लाए जा रहे हैं और 'मेड इन इंडिया' इंजनों को कई देशों में निर्यात किया जा रहा है। यह 'मेक इन इंडिया' पहल के निरंतर विस्तार को दर्शाता है तथा राष्ट्रीय गौरव को मजबूत करता है। उन्होंने कहा, 'एक मजबूत रेलवे

नेटवर्क सुविधाएं बढ़ाता है और उद्योगों तथा कृषि को बढ़ावा देता है।'

औद्योगिक महाशक्ति के रूप में होगी मजबूत स्थिति

श्री मोदी ने कहा कि गुजरात ने शिक्षा, आईटी, सेमीकंडक्टर और पर्यटन सहित कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसने इसे विभिन्न उद्योगों में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित किया है। यहां हजारों करोड़ रुपए के निवेश से एक प्रमुख सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जो वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में भारत की स्थिति को और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि दाहोद, वडोदरा, गोधरा, कलोल और हलोल ने सामूहिक रूप से गुजरात में एक उच्च तकनीक इंजीनियरिंग और विनिर्माण गलियारा स्थापित किया है। वडोदरा विमान विनिर्माण में तेजी से आगे बढ़ रहा है और यहां भारत का पहला गति शक्ति विश्वविद्यालय भी है। उन्होंने कहा कि भविष्य में गुजरात का यह क्षेत्र साइकिल और मोटरसाइकिल से लेकर रेलवे इंजन और विमान तक सब कुछ बनाने के लिए जाना जाएगा। इस तरह का उच्च तकनीक इंजीनियरिंग और विनिर्माण गलियारा वैश्विक स्तर पर दुर्लभ है, जो एक औद्योगिक महाशक्ति के रूप में गुजरात की स्थिति को मजबूत करता है।

जनजातीय समुदायों के उत्थान के लिए सरकार प्रतिबद्ध

श्री मोदी ने जोर देकर कहा, 'विकसित भारत के निर्माण के लिए जनजातीय क्षेत्रों का विकास आवश्यक है।' देश में जनजातीय समुदायों के उत्थान के लिए पिछले 11 वर्षों में अभूतपूर्व प्रयास किए गए हैं। राज्य में पहले जनजातीय बच्चों को विज्ञान की पढ़ाई करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब पूरे जनजातीय क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अच्छे कॉलेज, आईटीआई, मेडिकल कॉलेज और इन समुदायों को समर्पित दो जनजातीय विश्वविद्यालय उपलब्ध हैं। इन वर्षों में एकलव्य मॉडल स्कूलों का नेटवर्क काफी मजबूत हुआ है, जिससे जनजातीय छात्रों के लिए बेहतर शैक्षिक अवसर सुनिश्चित हुए हैं।

- **अब स्मार्टफोन, ऑटोमोबाइल, खिलौने, रक्षा उपकरण और दवाओं सहित कई तरह के उत्पादों का निर्यात कर रहा भारत**
- **रेल और मेट्रो तकनीक का विनिर्माण और इसे वैश्विक स्तर पर निर्यात भी कर रहा भारत**
- **ऑस्ट्रेलिया को मेट्रो कोच और इंग्लैंड, सऊदी अरब व फ्रांस को ट्रेन कोच का कर रहा निर्यात**
- **मैक्सिको, स्पेन, जर्मनी और इटली भी भारत से रेलवे से संबंधित कंपोनेंट आयात करते हैं**
- **'मेड इन इंडिया' इंजनों को कई देशों में किया जा रहा निर्यात, राष्ट्रीय गौरव को मिल रही मजबूती**

उन्होंने कहा कि दाहोद में ही कई एकलव्य मॉडल स्कूल हैं, जो जनजातीय शिक्षा को अधिक बढ़ावा दे रहे हैं।

देश भर में जनजातीय समुदायों के विकास के लिए किए जा रहे महत्वपूर्ण प्रयासों पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार जनजातीय गांवों के उत्थान के लिए एक बड़ी योजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि 'धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान' एक ऐतिहासिक पहल है, जिसके कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार लगभग 80 हजार करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। इस योजना के तहत गुजरात सहित देश भर के 60 हजार से अधिक गांवों में विकास कार्य किए जा रहे हैं। इन गांवों को जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए पक्के घर, बिजली, पानी, सड़क, स्कूल और अस्पतालों से सुसज्जित किया जा रहा है, जिससे समुदाय के लिए जीवनयापन की बेहतर स्थिति सुनिश्चित हो रही है।

सबसे सीमांत जनजातीय समुदायों के उत्थान के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार उन लोगों को प्राथमिकता देती है जिनकी लंबे समय से अनदेखी की गई है। पहली बार सरकार ने विशेष रूप से निर्बल जनजातीय समूहों को सहायता देने के लिए पीएम जनमन योजना शुरू की है, जो दशकों से आवश्यक सुविधाओं से वंचित रहे हैं। इस योजना के तहत जनजातीय गांवों में नए बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का विकास किया जा रहा है और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न किए जा रहे हैं, जिससे इन समुदायों के लिए अधिक आर्थिक और सामाजिक समावेश सुनिश्चित हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनजातीय समुदायों को सिकल सेल एनीमिया से मुक्त करने के लिए राष्ट्रीय मिशन के शुरू करके लाखों जनजातीय नागरिकों की जांच की जा चुकी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार पिछड़े क्षेत्रों के विकास में तेजी लाने के लिए प्रतिबद्ध है। ■

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह कोलकाता में आयोजित समारोह में बोले

फॉरेंसिक ऑडिट से बड़े-बड़े आर्थिक घोटालों का हो रहा खुलासा

- **केंद्र सरकार एक सुरक्षित, पारदर्शी और एविडेंस-बेस्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का कर रही निर्माण**
- **थानें जाने में बढ़ेगा भरोसा, न्यायपूर्ण कार्य प्रणाली बनाने को सरकार प्रतिबद्ध**
- **नई कानून व्यवस्था में साठ दिनों में हो रहे 60 प्रतिशत मामलों में आरोप पत्र दाखिल**
- **कोलकाता के फोरेंसिक लैब से पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिशा और नॉर्थईस्ट को एविडेंस बेस्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम डेवलप करने में मदद मिलेगी**

सहकार जागरण टीम

सरकार के आधुनिक दृष्टिकोण से सुरक्षित, पारदर्शी और एविडेंस-बेस्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के निर्माण में मदद मिली है। अपराध रोकने वाले, अपराधियों से दो कदम आगे रहने के लिए विज्ञान और स्पष्ट कानूनों का उपयोग होना जरूरी है। इससे अपराधियों के आगे निकलने की संभावना बिल्कुल समाप्त हो जाती है। फॉरेंसिक ऑडिट से अब बड़े-बड़े आर्थिक घोटाले भी बाहर आ रहे हैं। इससे हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी के नये भवन के उद्घाटन अवसर पर यह बात कही। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस आधुनिक लैब के माध्यम से पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिशा, असम, सिक्किम और नॉर्थईस्ट के सभी राज्यों को एविडेंस-बेस्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम डेवलप करने और एक हॉलिस्टिक अप्रोच की भूमिका का निर्वहन करने में मदद मिलेगी।

देश के तीन नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन में एविडेंस, फॉरेंसिक साइंस और दोषियों को सजा कराने में इनके महत्व

को समझाने, अपनाने और इन्हें हर पुलिस स्टेशन तक पहुंचाने में इस एफएसएल की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। उन्होंने बताया कि पूरे देश में एफएसएल का नेटवर्क तैयार कर तीन चार राज्यों का क्लस्टर बना जाएगा। सरकार इसी के मार्फत वहां के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एविडेंस-बेस्ड बनाने का प्रयास कर रही है। क्लस्टर अप्रोच से फॉरेंसिक साइंस को थाने तक पहंचाने तक की अप्रोच, फॉरेंसिक साइंस को एविडेंस में महत्व देने के लिए हर कोर्ट तक पहुंचाने की प्रक्रिया और हर थाने में जांच अधिकारी को इसका महत्व समझाने का अभियान जनवरी, 2026 से शुरू किया जाएगा।

पूरे देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को तर्क की जगह एविडेंस-बेस्ड बनाया जाएगा जिससे दोषियों को संदेह का लाभ नहीं मिल सकेगा और पीड़ित को न्याय मिलेगा। श्री शाह ने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया तभी संभव है जब पुलिस थाने, पब्लिक प्रॉसीक्यूटर और कोर्ट इस पूरी प्रक्रिया का महत्व समझकर उसे अपनाएं और कामकाज में महत्व दें। एफएसएल का नेटवर्क तैयार कर क्लस्टर अप्रोच से जटिल मामलों में विशेषज्ञों की मदद से निर्णय पर पहुंचने के साथ पूरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन होगा। नारकोटिक्स संस्करण 2.0 और एक्सप्लोसिव संस्करण 2.0 की भी विधिवत शुरूआत की गई। इससे देशभर की फॉरेंसिक साइंस लैब्स को कई प्रकार के काम करने में सरलता प्रदान करेंगे।

21वीं सदी में हम हमारे ट्रांसेक्शन्स, कम्युनिकेशन, आइडेंटिटी और बेसिक डिटेल्स एक ही जगह पर स्टोर हो रहे हैं तो अपराध का स्वरूप भी तेजी से बदल रहा है। इसके लिए न्याय प्रणाली को उसी के अनुरुप खुद को बदलकर मुस्तैद होना होगा।

भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारत के लोगों द्वारा चुनी गई संसद द्वारा भारत के लोगों के संविधान प्रदत्त अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए कानून हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार 160 साल पुराने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों को

खत्म कर नए भारत के नए कानून लाई है। न्याय दिलाने की दिशा में ये एक क्रांतिकारी बदलाव है क्योंकि अब प्रमाण के अभाव में दोषी नहीं छूट सकेंगे। इन कानूनों में आने वाले 100 वर्षों तक तकनीक में आने वाले संभावित सभी बदलावों को समाहित कर अभी से परिभाषित कर दिया गया है।

समय पर मिलेगा न्याय

श्री शाह ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों में क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल में तकनीक के उपयोग को कानूनी आधार दिया गया है। सात वर्ष से अधिक सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक साइंस टीम की विज़िट अनिवार्य की गई है। इन कानूनों में समय पर न्याय मिलने की चिंता की गई है। दो महीने के भीतर आरोपपत्र दाखिल करने का प्रावधान किया गया है। लगभग 60 प्रतिशत मामलों में 60 दिन में आरोपपत्र दाखिल होने लगे हैं जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। ट्रायल इन एब्सेंशिया के माध्यम से कानून की पकड़ से बाहर रहने वालों का उनकी अनुपस्थिति में हम ट्रायल करेंगे। सजा सुनाई जाएगी। अंतरराष्ट्रीय समझौतों का उपयोग कर उन्हें वापस लाया जाएगा। देश के 17,184 थाने आधुनिक नेटवर्क से जुड़े होने से सब ऑनलाइन हैं। उन सभी का डेटा एकसाथ जेनेरेट हो रहा है।

केंद्र सरकार ने हर ज़िले में एक फॉरेंसिक मोबाइल वैन के लिए सहायता देने का ऑफर दिया गया है। कई राज्यों ने अपने यहां एफआईआर की संख्या देखकर वैन की संख्या खुद बढ़ा ली है। नेशनल फोरेंसिक साइंस युनिवर्सिटी के 16 परिसर स्वीकृत हो चुके हैं। इनमें सात स्थापित हैं। इसके अलावा हर बड़े राज्य में एक एनएफएसयू बनाए जाएंगे। देशभर के 26 परिसरों से 36 हजार विद्यार्थी डिग्री, डिप्लोमा और पीएचडी के साथ बाहर निकलेंगे। जबकि हमारी आवश्यकता 30 हजार प्रतिवर्ष है। इस प्रकार आवश्यकता के अनुसार 'ह्यूमन रिसोर्स' बनाने का काम हम एडवांस में पूरा कर चुके हैं।

कुल 1300 करोड़ रुपए की लागत से एनएफएसयू के नौ और कैंपस बनेंगे। जबकि 860 करोड़ रुपए की लागत से सात नई सीएफएसएल बनाई जाएंगी जो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल और बिहार में होंगी। राज्यों की फॉरेंसिक साइंस सुविधाओं को सपोर्ट देने का काम केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने किया है। उन्होंने कहा कि हम 2080 करोड़ रुपए की फॉरेंसिक क्षमताओं के आधुनिकीकरण की योजना भी ला रहे हैं और 200 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल फॉरेंसिक डेटा सेंटर की स्थापना भी करने की योजना है।

श्री शाह ने कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने आजादी की स्पिरिट को संविधान में भरने का काम किया लेकिन उसे जमीन पर उतारने का काम हम बहुत देर से शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा दायित्व है कि गरीब से गरीब व्यक्ति सर ऊंचा कर सिस्टम पर भरोसे के साथ थाने में जा सके और न्याय प्रक्रिया से उसे कम से कम समय में न्याय मिल सके।■

जिनेवा में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में बोले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना

सहकार जागरण टीम

▶▶ **समावेशन भारत के स्वास्थ्य सुधारों के मूल में है, जो 58 करोड़ लोगों को कवर करती है और मुफ्त उपचार प्रदान करती है**

▶▶ **समावेशन, एकीकृत दृष्टिकोण और सहयोग पर निर्भर करता है स्वस्थ दुनिया का भविष्य**

स्वस्थ दुनिया का भविष्य समावेशन, एकीकृत दृष्टिकोण और सहयोग पर निर्भर है। समावेशन ही भारत के स्वास्थ्य सुधारों का आधार है, जो आयुष्मान योजना के तहत 58 करोड़ देशवासियों को कवर कर मुफ्त उपचार प्रदान करती है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जिनेवा के 'वर्ल्ड हेल्थ असेंबली' के 78वें सत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन विचारों को साझा किया। उन्होंने आयोजन की थीम 'वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ' का जिक्र करते हुए इस बात पर खुशी जाहिर की और कहा कि यह वैश्विक स्वास्थ्य के लिए भारत के विजन के अनुरूप है। श्री मोदी ने कहा कि भारत की आयुष्मान योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो मुफ्त उपचार प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि हाल ही में इस योजना को 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीयों को कवर करने के लिए विस्तारित किया गया है। भारत के हजारों 'हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर' के व्यापक नेटवर्क की जानकारी देते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये स्वास्थ्य केंद्र कैंसर, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों की शुरूआती जांच करने के साथ-साथ इनका पता लगाने की सुविधा प्रदान करते हैं। उन्होंने हजारों सार्वजनिक फार्मेसियों की अहम भूमिका का भी जिक्र किया, जो काफी कम कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं प्रदान करती हैं।

स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका

श्री मोदी ने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका का जिक्र किया और कहा कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण को ट्रैक करने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म और 'यूनिक डिजिटल हेल्थ आइडेंटिटी सिस्टम' जैसी भारत की डिजिटल पहलों से सूचनाओं, लाभों, बीमा और रिकॉर्ड्स को एकीकृत करने में मदद मिल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टेलीमेडिसिन की सुविधा से अब कोई भी मरीज अपने डॉक्टर से बहुत दूर नहीं है। भारत की मुफ्त टेलीमेडिसिन सेवा ने 34 करोड़ से अधिक देशवासियों को चिकित्सा परामर्श प्रदान किया है। भारत की स्वास्थ्य पहलों के सकारात्मक प्रभावों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी स्वास्थ्य व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है और इससे नागरिकों के कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय में उल्लेखनीय गिरावट आई है।■

दिल्ली में यमुना की सफाई, पेयजल और सीवेज व्यवस्था पर बोले श्री अमित शाह

जल आपूर्ति के लिए पाइप लाइनों में लीकेज रोकने के साथ जल वितरण संरचना को और सुदृढ़ बनाने की जरूरत

सहकार जागरण टीम

यमुना हमारे लिए सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि यह हमारी आस्था का प्रतीक भी है। इसलिए इसकी स्वच्छता मोदी सरकार की प्राथमिकता है। इन संकल्पों को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक में दोहराया। उन्होंने यमुना की सफाई, दिल्ली में पीने के पानी और सीवेज व्यवस्था के लिए एक समग्र दृष्टिकोण के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उच्चस्तरीय बैठक में श्री शाह ने निर्देशित किया कि दिल्ली में यमुना को पुनः निर्मल व प्रवाहयुक्त करने, पीने के पानी की व्यवस्था को उच्चस्तरीय करने और ड्रेनेज सिस्टम को लेकर जो भी योजना बने, उसमें अगले 20 वर्षों की जरूरतों और विकास के मानकों को ध्यान में रखा जाए।

यमुना हमारे लिए सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि आस्था का भी प्रतीक हैं

उन्होंने कहा कि यमुना की सफाई में दिल्ली जल बोर्ड की महत्वपूर्ण भूमिका है और इसलिए इसका सुदृढ़ीकरण बहुत जरूरी है। श्री शाह ने दिल्ली जल बोर्ड में खाली पदों को तत्काल भरे जाने पर जोर दिया और इसे विभाग की प्रभावी कार्यकुशलता के लिए अपरिहार्य कहा।

दिल्ली में जल वितरण क्षमता बढ़ाने पर जोर

श्री शाह ने दिल्ली में जल वितरण क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि पूरी दिल्ली को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल का प्रबंधन बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जल आपूर्ति के लिए जल बोर्ड पाइपलाइनों में लीकेज को रोकने के साथ जल वितरण संरचना को और सुदृढ़ बनाए। इस व्यवस्था को मजबूती देने और पानी की सफाई की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए श्री शाह ने नालों से गाद हटाने के लिए विश्व-स्तरीय तकनीक के उपयोग पर भी जोर दिया।

देश में जल प्रबंधन को उच्चस्तरीय बनाने के लिए उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय का आह्वान किया कि उसे सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनानी चाहिए, जिससे उनकी गुणवत्ता, रख-रखाव और डिस्चार्ज के मानदंड स्थापित किए जाएं। श्री शाह ने कहा कि इस एसओपी को देश के अन्य सभी राज्यों के साथ साझा करने का भी सुझाव दिया।■

अन्न भंडारण से जुड़ेंगे ज्यादा से ज्यादा पैक्स

सहकार जागरण टीम

विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना पैक्स की आमदनी और ग्रामीण रोजगार को बढ़ाने में मददगार साबित होने वाली है। इस योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सहकारिता क्षेत्र को दी गई है जिसके तहत प्राथमिक सहकारी ऋण समितियां (पैक्स) अनाज भंडारण के लिए गोदामों, कस्टम हायरिंग सेंटर और कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रही हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में इस योजना की समीक्षा के लिए हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्यों को अपने स्तर पर अधिक से अधिक पैक्स को इस योजना में शामिल करने का निर्देश दिया जाए। साथ ही, राज्य स्तरीय मार्केटिंग फेडरेशनों को भी इससे जोड़ा जाए ताकि एक संपूर्ण सहकारी आपूर्ति श्रृंखला विकसित की जा सके।

- **राज्यों को अधिक से अधिक पैक्स को इस योजना में शामिल करने और राज्य स्तरीय मार्केटिंग फेडरेशनों को भी इससे जोड़ने का निर्देश देने का फैसला**
- **एफसीआई, एनसीसीएफ, नैफेड और राज्य वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन को भी पैक्स को अधिक से अधिक गोदामों से जोड़ने के दिए निर्देश**

केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने अन्न भंडारण योजना में पैक्स की व्यापक भागीदारी पर बल देते हुए बैठक में कहा कि यह जरूरी है कि पैक्स को इस योजना का अभिन्न हिस्सा बनाया जाए ताकि उसकी वित्तीय व्यवहार्यता और सामाजिक प्रभावशीलता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने बैठक में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), एनसीसीएफ, नैफेड और राज्य वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशनों को पैक्स को अधिक से अधिक गोदामों से जोड़ने के लिए ठोस दिशा-निर्देश दिए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के विजन को साकार करने की दिशा में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना एक बड़ा कदम है। देश में आर्थिक प्रगति को मापने के दो प्रमुख मापदंड हैं- सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और रोजगार सृजन। अन्न भंडारण योजना इन दोनों पहलुओं को सशक्त बनाने का माध्यम है, जिसका उद्देश्य पैक्स की आमदनी बढ़ाने के साथ-साथ ग्रामीण रोजगार के अवसरों को सृजित करना है। बैठक में श्री शाह ने कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) के अंतर्गत ऋण अवधि के विस्तार से पैक्स की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।

इस बैठक में सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर एवं श्री मुरलीधर मोहोल के अलावा सहकारिता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मंत्रालय, एफसीआई, नाबार्ड, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) सहित अन्य संगठनों के अधिकारी उपस्थित थे। श्री अमित शाह ने सभी संगठनों से समन्वय के साथ योजना को समयबद्ध और प्रभावशाली तरीके से लागू करने का आह्वान किया ताकि यह योजना 'आत्मनिर्भर भारत' और 'सहकार से समृद्धि' के लक्ष्य की पूर्ति में मील का पत्थर साबित हो।

इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत पांच वर्ष में कुल सात करोड़ टन अतिरिक्त खाद्यान्न भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी। इस पर एक लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी। मौजूदा समय में देश की भंडारण क्षमता कुल खाद्यान्न उत्पादन के आधे से भी कम करीब 47 प्रतिशत ही है। फसल वर्ष 2024-25 के तीसरे अग्रिम अनुमान में देश का खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 35.40 करोड़ टन रहने का अनुमान सरकार ने जताया है, जबकि इसकी तुलना में खाद्यान्न भंडारण की कुल क्षमता 14.5 करोड़ टन ही है। विश्व की सबसे बड़ी आबादी की पुख्ता खाद्य सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार जहां खाद्यान्न की पैदावार बढ़ाने के लिए उत्पादकता पर जोर दे रही है, वहीं उपज के सुरक्षित भंडारण को भी उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। पैक्स के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में अनाज के गोदाम बनाने की इस योजना से न सिर्फ गांवों में ही अनाज भंडारण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि वर्तमान में भंडारण के दौरान अनाज की हो रही क्षति को भी रोका जा सकेगा। यह ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खोलेगा।■

त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बोर्ड गठित

सहकार जागरण टीम

देश की पहली सहकारी यूनिवर्सिटी का संचालन जल्द से जल्द शुरू करने को लेकर केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय प्रयासरत है। गुजरात के आणंद स्थित ग्रामीण प्रबंधन संस्थान (इरमा) में नवगठित त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नियुक्त करने के बाद अब मंत्रालय ने इसकी पहली गवर्निंग बोर्ड का भी गठन कर दिया है। 19 सदस्यीय इस बोर्ड में सहकारिता क्षेत्र के दिग्गज श्री दिलीप संघाणी और श्री सतीश मराठे को भी नामित किया गया है। देश में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के कदम के रूप में आजादी के बाद पहली बार सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है। इस संबंध में संसद द्वारा कानून बनाए जाने के बाद इसमें तेजी आ गई है।

गवर्निंग बोर्ड 'त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी अधिनियम, 2025' की धारा 21(2) के तहत गठित हुआ है और यह 27 मई, 2025 से प्रभावी हो गया। इस बोर्ड में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, सहकारी संस्थानों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। इसमें यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. डॉ. जेएम व्यास, सहकारिता सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी सहित कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण तथा मत्स्य पालन मंत्रालय के सचिवों को जगह दी गई है। इनके अलावा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और नाबार्ड के अध्यक्ष, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) के सीईओ, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक (वित्तीय समावेशन एवं विकास विभाग) श्री नीरज निगम और यूनिवर्सिटी के फाइनेंस ऑफिसर और रजिस्ट्रार (सदस्य सचिव) को भी बोर्ड में रखा गया है।

- **19 सदस्यीय गवर्निंग बोर्ड में एनसीयूआई अध्यक्ष श्री दिलीप संघाणी भी बने सदस्य**
- **इफको, कृभको, नैफेड और एनसीसीएफ के अध्यक्ष रोटेशन आधार पर सदस्य के रूप में करेंगे काम**

गवर्निंग बोर्ड के चार नामित सदस्यों में एनसीयूआई के अध्यक्ष श्री दिलीप संघाणी, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक श्री सतीश मराठे, सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की एमडी और सीईओ श्रीमती आरती पाटिल और मणिपुर स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट जीना पोटसांगबम का नाम शुमार है। सहकारिता क्षेत्र के इन दिग्गजों की विशेषज्ञता से जमीनी अनुभव और वित्तीय अनुशासन को मजबूती मिलेगी। साथ ही, महिला नेतृत्व और पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रतिनिधित्व को भी बल मिलेगा। श्री संघाणी और श्री मराठे का राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सहकारी सशक्तीकरण के लिए श्री संघानी लंबे समय से वकालत करते रहे हैं, जबकि सहकार भारती के संस्थापक सदस्य श्री मराठे के आरबीआई के वित्तीय प्रशासन के अनुभव से बोर्ड के संचालन में जमीनी स्तर की गहराई और नियामकीय अंतर्दृष्टि में मदद मिलेगी।

भारत के सबसे बड़े शहरी सहकारी बैंक सारस्वत सहकारी बैंक की एमडी और सीईओ आरती पाटिल को बोर्ड में जगह देने का मकसद सहकारी नेतृत्व में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को उजागर करना और उनकी बैंकिंग सूझबूझ एवं सारस्वत बैंक की डिजिटल परिवर्तन पहल को सहकारी शिक्षा में बढ़ावा देना है। जीना पोत्संगबाम की नियुक्ति सहकारी शिक्षा रणनीति को आकार देने में भौगोलिक और सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की केंद्र की प्रतिबद्धता को दशार्ती है। पोत्संगबाम का बोर्ड में शामिल होना देश के सहकारी आंदोलन में उत्तर-पूर्व की बढ़ती भागीदारी का प्रतीक है, जो समावेशी विकास के व्यापक लक्ष्य के साथ क्षेत्रीय आकांक्षाओं को जोड़ता है।

क्षेत्रीय दृष्टिकोण को यूनिवर्सिटी की नीतियों में शामिल करने के लिए मध्य प्रदेश, असम, केरल और गुजरात के सहकारिता विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव को रोटेशन आधार पर नामित किया गया है। देश की प्रमुख सहकारी संस्थाओं इफको, कृभको, नैफेड और एनसीसीएफ के अध्यक्ष भी रोटेशन के आधार पर बोर्ड के सदस्य के रूप में काम करेंगे। इस रोटेशनल मॉडल का उद्देश्य विविध विशेषज्ञता से समृद्ध एक गतिशील नीति ढांचा प्रदान करना है। सभी नामित सदस्यों का कार्यकाल तीन साल का होगा। सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए इस कदम से पूरे देश में ग्रामीण विकास, वित्तीय साक्षरता और विकेंद्रीकृत आर्थिक सशक्तीकरण के एक नए युग की शुरूआत होगी।■

विशेष आलेख

डॉ एसएलएनटी श्रीनिवास

गांव-गांव तक कोऑपरेटिव डेयरी से सुधरेगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के संकल्प को पूरा करने के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। देश के पहले केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह सहकारिता क्षेत्र के लिए नया लक्ष्य निर्धारित कर उसे प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए डेयरी क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया है। इसके लिए डेयरी पैक्स के गठन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सहकारिता मंत्री श्री शाह ने अगले कुछ वर्षों के भीतर देश में दो लाख पैक्स के गठन का लक्ष्य दिया है, जिसमें कृषि, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र को शामिल किया जा रहा है। सरकार की इस पहल से कृषि के साथ डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। नई आर्थिक पहल का मार्ग भी प्रशस्त होगा। उन्नत कृषि को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी के बेहतर प्रयोग पर जोर दिया जा रहा है।

प्राथमिक सहकारी समितियां (पैक्स) कृषि विकास के लिए सहकारिता मंत्रालय ने ड्रोन दीदी को बढ़ावा दिया है जिसके तहत राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं ने ड्रोन विकसित करने और पैक्स को देने की योजना तैयार की है। दूसरी हरित क्रांति में ड्रोन तकनीक का उपयोग एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है, ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों द्वारा ड्रोन को घर घर तक पहुंचाने का क्रांतिकारी प्रयास किया जा रहा है। सहकार से समृद्धि के क्रम में सहकारी समितियां एक संगठन के रूप में काम कर रही हैं, जो बहुउद्देश्यीय सेवाएं सदस्यों और समुदायों में विश्वास बनाए रखने और उनकी आर्थिक उन्नति के लिए बहुउद्देश्यीय सेवाओं में काम कर रही हैं। सहकारी समितियां भविष्य की जरूरत आधारित कई सेवाओं का संचालन करेंगीं, हालांकि खुद सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिरता उनकी वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करती है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने देश में उन्नत कृषि के लिए आधुनिक कृषि मशीनरी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के बाबत कई योजनाओं को सहकारिता से जोड़ा है। आंध्रप्रदेश कोणासीमा जिले में देवागुप्ताम पैक्स द्वारा ड्रोन कार्यक्रम की शुरूआत पहली बार किया गया। सहकारी संस्थाओं के माध्यम से 1.95 करोड रूपए की लागत से 21 ड्रोन तैयार कराए गए हैं। सहकारी समितियों की हिस्सेदारी बढ़ने से सहकारी बैंकों से उन्हें अति रियायती दरों (चार प्रतिशत की ब्याज) ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। सहकारी समितियों को छूट के तौर पर यह प्रावधान किया गया है कि समितियां अगर सही समय पर ऋण का भुगतान कर देती है तो एग्रीकल्चर इंवेस्टमेंट फंड के तहत सहकारी समिति को तीन प्रतिशत ब्याज तक की सब्सिडी दी जाती है।

कृषि प्रौद्योगिकी के माध्यम से सहकारी समितियों के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाना एक महत्वपूर्ण पहलू है। केंद्र और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को इस तकनीकि के उपयोग के लाभ के बारे में पूरी जानकारी दें। सहकारी क्षेत्र की शीर्ष संस्था (एनसीयूआई) के शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से पीएम किसान ड्रोन और अन्य प्रौद्योगिकी वाली योजना की जानकारी किसानों तक पहुंचाई जा रही है। देवागुप्ताम पैक्स मानव संसाधन प्रबंधन जैसे ड्रोन पायलट और को-पायलट का भी प्रबंधन संभाल रही है। कुल मिलाकर एक अति महत्वकांक्षी परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए सभी स्तर पर बेहतर प्रबंधन व्यवस्था तैयार की गई है। किसानों के तकनीकी पहलू समझाने के लिए एनसीयूआई इफको की टीम प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित कर रही है, जिला स्तर पर डेमो के माध्यम से स्प्रे कराए जा रहे हैं। ड्रोन का अधिक से अधिक प्रयोग कृषि कार्यों के लिए हो, इसके लिए महिला ड्रोन पायलट तैयार किए जा रहे हैं। सरकार ने देशभर में दो लाख ड्रोन दीदी पायलट के रूप में काम करेंगीं, इसमें स्वयं सेवी संगठनों की महिलाओं को वरीयता दी जा रही है, जिससे वह प्रतिमाह एक लाख रुपए तक की आमदनी भी कर सकती हैं।

ड्रोन प्रबंधन के लिए सरकार हर पहलू पर नजर रखें है, पैक्स को उपलब्ध कराए गए ड्रोन की नियमित मॉनिटरिंग पर भी ध्यान दिया जा रहा है, आंध्रप्रदेश में पैक्स द्वारा ड्रोन परियोजना संचालन के अब तक के परिणाम काफी बेहतर हैं। ड्रोन के साथ ही अन्य जरूरी उपकरण स्प्रेयर और लोडर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे खेतों में ड्रोन को आसानी से पहुंचाया जा सके। सहकारिता प्रबंधन संस्थानों में विशेष पाठ्यक्रमों के माड्यूल योजनाओं के क्रियान्वयन में काफी सहायक होते हैं, एनसीयूआई का टीओटी या प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण देशभर के सहकारी संस्थानों में शुरू किया गया जिससे सहकार से समृद्धि के लक्ष्य को मजबूत हो रहा है। ■

वरिष्ठ संकाय सदस्य, आईसीएम (इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट) हैदराबाद

एनसीयूआई, नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केंद्र (एनसीसीई) ने भारतीय मत्स्य सहकारी समितियों के अध्यक्षों एवं निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सरकारी योजनाओं, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड और मत्स्य व्यवसाय में प्रौद्योगिकी-संचालित डिजिटलीकरण के बारे में विविध पहलुओं पर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

भारत की महिला सहकारी समितियों के अध्यक्षों और निदेशकों के लिए राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केंद्र ने एनसीयूआई में तीन दिवसीय नेतृत्व विकास कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें एनसीयूआई के अध्यक्ष श्री दिलीप संघाणी, एनसीयूआई के मुख्य कार्यकारी डॉ. सुधीर महाजन और एनसीयूआई की उप मुख्य कार्यकारी श्रीमती सावित्री सिंह ने प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया।

एनसीयूआई के राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केंद्र (एनसीसीई) में भारत की उपभोक्ता सहकारी समितियों के पदाधिकारियों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न राज्यों के 49 प्रतिनिधियों ने भागीदारी की और सहकारी दर्शन और उपभोक्ता सहकारी समितियों के लिए कानूनी प्रावधान जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन किया।

एनसीयूआई के राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केंद्र (एनसीसीई) ने सहकारी शिक्षा कर्मियों के लिए प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सात राज्यों के जिला और राज्य सहकारी संघों के साथ-साथ अन्य सहकारी समितियों के प्रशिक्षक 31 प्रतिभागियों ने भागीदारी की और सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण में कौशल बढ़ाने के गुर सीखा।

एनसीसीई ने नई दिल्ली में भारतीय उपभोक्ता सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मानव संसाधन प्रबंधन एवं संचार तथा सहकारी व्यवसाय विकास के लिए सोशल मीडिया एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग की जानकारी दी गई। एनसीयूआई के कार्यकारी निदेशक श्री वेद प्रकाश सेतिया ने नई सहकारी नीति, एमएससीएस अधिनियम और सहकारी समितियों पर इसके प्रभाव पर जानकारी दी।

एनसीयूआई ने अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के एक पहल के रूप में इफको फूलपुर ईकाई के समर्पित टेक्नोक्रेट्स के लिए 'सहकारिता और सहकारी प्रबंधन' पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, जो कि सहकारी नेतृत्व को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और लचीला सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए प्रबंधकीय क्षमताओं को बढ़ाने पर केंद्रित रहा।

पिछले एक दशक में हमारी सरकार ने लोगों को गरीबी की स्थिति से निकालने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सभी प्रमुख योजनाओं ने गरीबों के जीवन को बदल दिया है। पीएम आवास योजना, पीएम उज्वला योजना, जन धन योजना और आयुष्मान भारत जैसी पहलों ने आवास, स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन, बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को बढ़ाया है। डीबीटी, डिजिटल समावेशन और ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर बल ने पारदर्शिता और अंतिम सिरे तक लाभों की त्वरित डिलीवरी सुनिश्चित की है। इसमें सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचे और समावेशन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसी के कारण 25 करोड़ से अधिक लोगों ने गरीबी को मात दी है।

- श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

NCUI हाट

एनसीयूआई हाट, एनसीयूआई और कम प्रचलित सहकारी संस्थाओं के बीच नये आयाम स्थापित कर रहा है, जो उत्पादों की बिक्री और प्रदर्शनी के लिए एक सामान्य प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है। अब एनसीयूआई हाट अपने नवीन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी *'सहकार से समृद्धि'* को साकार करने के लिए उपर्युक्त वातावरण का निर्माण कर रहा है।

CEAS-LMS Portal

कोऑपरेटिव एक्सटेंशन एंड एडवाइज़री सर्विसेज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (**CEAS-LMS**) अपने तरह का पहला ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, जो सहकारी सदस्यों को सहकारिता से जुड़ी सेवाओं की जानकारी देता है। यह तीन चरण में काम करता है:

1. **LMS:** लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत पंजीकृत सदस्यों को प्रत्येक चरण की सहकार शिक्षा दी जाती है।
2. **QMS:** क्यूरी मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा मंच है जहां उपयोगकर्ता सहकारिता से जुड़े अपने मुद्दे रख सकते हैं, जिससे उन्हें तुरंत गुणवत्ता परक सलाह मिल सके।
3. **CRC:** कोऑपरेटिव रिसोर्स सेंटर सभी हितधारकों का प्लेटफार्म है, जिसके माध्यम से सहकारिता से जुड़े सभी सदस्य जानकारियों का आदान प्रदान कर सके।

https://ncuicoop.education/

नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के लिए राजीव शर्मा द्वारा प्रकाशित और एनसीयूआई प्रिंटिंग प्रेस, बी-81, सेक्टर-80, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में मुद्रित। संपादक : राजीव शर्मा

Postal Registration No: DLHIN/25/A0141
Published on 25.07.2025 Applied for Registration/ Exempted

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ